बिहार विधान-सभा सचिवालय

तिथि ५ जून, १९७० ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में शुक्रवार, तिथि ५ जून, १९७० को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष, श्री रामनारायण मंडल के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ ।

अल्पसूचित प्रश्नोत्तर

बिहार के अलकोहलिक वीभरेज की बिक्री में कमी

५५ । श्री राजमंगल मिश्र—क्या मंत्री, उत्पाद विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में अलकोहलिक वीभरेज २६ रुपया २० पैसा प्रति एल० पी० लिटर है;

(२) क्या यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश एवं बंगाल का रेट कम होने से बिहार के अलकोहलिक वीभरेज की बिक्री कम होती है, यदि हां तो इसका राज्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

श्री सेत हेम्ब्रम—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(२) राज्य-सरकार की नीति रही है कि कम-से-कम खपत में अधिक-से-अधिक राजस्व प्राप्त हो । वर्त्तमान कर-दर से जो प्रभाव पड़ा है उसके वास्तविक स्वरूप की समीक्षा की जा रही है तथा शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा ।

(*) श्री राजमंगल मिश्र—क्या सरकार को मालूम है कि बंगाल का रेट २३ रुपया और यू० पी० का २१ रुपया ही है ?

श्री दारोगा प्रसाद राय—यह सही है कि बिहार से बंगाल और यू० पी० का रेट कम है । हमने जो २६ रुपया तय किया है इसमें सेल्स टैक्स इन्क्लूडेड है । सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से इस संबंध में बातचीत चल रही है जिसमें सब जगह के रेट में एकता हो जाय ।

श्री राजमंगल मिश्र—क्या सरकार को मालूम है कि बंगाल में टैक्स है ही नहीं और यू० पी० में यहां से कम है ?

प्रश्न के उत्तर का दो जवाब हैं—एक गलत है और एक ठीक है। आपको आदेश देना चाहिए कि इस तरह का उत्तर देना अनुचित है।

ऐसे मामले में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उत्तर आने पर प्रीभीलेज मोशन भी आ सकता है। खैर, इसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। आपने कह दिया कि पढ़ लिया जाय। यह तो मानो हुई बात है कि माननीय मंत्री पढ़कर आते हैं। इसलिए यह अभियोग मंत्री पर आ सकता है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—इसमें कोई विरोधाभाष नहीं है यह बिलकुल सीधी बात है कि उन गाँवों के दोनों प्लौटों में जंगल की जमीन है, उनको जमीन नहीं ली गई है।

श्री राम एकबाल सिंह—इसको आपने स्थगित कर दिया है।

(इस अवसर पर कुछ हल्ला होने लगा।)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव—अध्यक्ष महोदय, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, इस पर आपकी व्यवस्था होनी चाहिए। आपने अपनी व्यवस्था दे दी है कि उत्तर में विरोधाभाष है। आपकी व्यवस्था हो गई है कि उत्तर गैरजवाबदेही के साथ दिया गया है। अब इसके लिए मैंने व्यवस्था की मांग की है कि जिस अफसर ने ऐसा उत्तर भेजा है उनके लिए तथा मंत्री के लिए अब व्यवस्था दें।

श्री दारोगा प्रसाद राय—इसकी जांच-पड़ताल की जायगी।

अध्यक्ष—मैं इसको स्थगित करता हूँ।

१९६९ में जंगल विभाग से राज्य सरकार को आय

६७४। श्री राजमंगल मिश्र—क्या मंत्री, वन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) बिहार प्रान्त में कितने एकड़ में जंगल है;

(२) (क) कितनी आमदनी १९६९ में जंगल विभाग से सरकार को हुई,

(ख) कितना खर्च उस साल सरकार का हुआ;

(३) क्या सरकार बतायेगी कि कितने और क्षेत्र में सरकार जंगल लगाना चाहती है?

श्री बागुन सोम्बरूई—(१) बिहार में ३०,७०० वर्ग किलोमीटर में जंगल है।

(२) (क) वन विभाग को १९६९-७० में विभिन्न वन स्रोतों से ३२८·६१ लाख रु० की आय हुई है।

(ख) वन विभाग द्वारा १९६९-७० में २३६·७२ लाख रुपया खर्च किया गया है

जिसका विवरण निम्नलिखित है :—

(क)	गैर-योजना खर्च	..	१४१·६० लाख रुपया ।
(ख)	योजना पर व्यय	..	९५·१२ लाख रुपया ।
	कुल खर्च	..	२३६·७२ लाख रुपया ।

(३) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में (१९६९-७० से १९७३-७४) करीब १·४० लाख एकड़ वन भूमि पर वनरोपन और भू-संरक्षण कार्य का प्रस्ताव है ।

*श्री राज मंगल मिश्र—मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या उत्तर बिहार में जंगल लगाने का प्लान है ?

श्री बागुन सोम्बरूई—हाँ, उत्तर बिहार में वनरोपन करने का हमलोगों का विचार है ।

श्री राम राज प्रसाद सिंह—खंड (२) के उत्तर में बताया गया है कि वन विभाग को १९६९-७० में विभिन्न वन स्रोतों से ३२८·६१ लाख रुपए की आय हुई है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आमदनी के हिसाब से अधिक खर्च कितना हुआ है ।

अध्यक्ष—इसको मैं स्थगित करता हूँ ।

चीनी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण

६८० । श्री जनार्दन तिवारी—क्या मंत्री, ईख विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने चीनी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय किया है, यदि हां, तो कब से ?

श्री जब्बार हुसैन—चीनी उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए और इसके राष्ट्रीयकरण पर प्रतिवेदन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया है । उक्त समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई होगी ।

श्री जनार्दन तिवारी—उत्तर में कहा गया है कि 'चीनी उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जाँच करने के लिए और इसके राष्ट्रीयकरण पर प्रतिवेदन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया है,' मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें कौन लोग हैं ?

श्री जब्बार हुसैन—एक सप्ताह पहले माननीय सदस्य नहीं थे, यह सवाल आया था और जवाब सदन की मेज पर रख दिया गया था ।